के लिए कृतक बल द्वारा मूल्यांकित किया गया है) निम्नवत है :—

वर्ष	अनुमानित वार्षिक मांग
1985 86	92,600
1986-87	1,02,000
1987-88	1,12,000
1988-89	1,23,500
1989-90	1,36,000

विवरण

1985-86 के दौरान ट्रैक्टरों की राज्य-वार बिक्री

क्रम सं.	राज्य	ट्रैक्टरों की बिक्री
1	आन्ध्र प्रदेश	4016
2.	असम	358
3.	बिहार	3512
4.	गुजरात	3972
5.	हरियाणा	9115
6.	हिमाचल प्रदेश	85
7.	जम्मू तथा कश्मीर	68
8.	कर्नाटक	2092
9.	केरल	341
10	मध्य प्रदेश	4966
11	महाराष्ट्र	3504
12.	मणिपुर	7
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	206
16.	पंजाब	13761
17.	राजस्थान	6162
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	2792
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	18135
22.	प. बंगाल	815
23.	संघ राज्य क्षेत्र	100
	अन्य	1006
	योग	75079

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

1505. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने वर्षों की सेवा के पश्चात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में आवास प्रदान किया जाता है; और

(ख) चालू आबंटन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किस प्राथमिकता तारीख तक सरकारी आवास आवंटित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह): (क) विभिन्न टाइप के आवासों के लिये लगभग 15 से 29 वर्ष ।

(ख) चालू आबंटन वर्ष के दौरान पूर्ण की जाने वाली सम्भावित अग्रता तिथि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि खाली होने वाले क्वार्टरों की संख्या का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

परन्तु विद्यमान तारीखें निम्नलिखित हैं :—

टाईप	वर्ष
टाईप-ए	196
टाईप-बी	195
टाईप-सी	196
टाईप-डी	195
टाईप-ई	197

"अकाल राहत कार्यक्रम" के अधीन बांधों की संख्या

1506. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां पर "अकाल राहत कार्यक्रम" के अन्तर्गत बांधों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या इन बांधों को मानसून के प्रारम्भ से पूर्व पूरा करने की योजना है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ बांधों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन बांधों को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक क्या योजना बनायी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द): (क) से (घ) विपदा-राहत कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा हाथ में लिये जाते हैं। अलग-अलग कार्यों का ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है।

Government accommodation to the employees of Parliament Secretariats

1507. SHRI ASWANI KUMAR: Will the Minister URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2158 given in the Rajya Sabha on the 16th August, 1985 and state :—

(a) what is the number of quarters allotted to the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, separately in the DIZ area at Delhi out of 140 quarters constucted since 1981 ;

(b) what are the reasons that quarters which were constructed out of the funds alloted to the 'Construction of Quarters for Parliament Secretariat" have been diverted to other Ministries and Departments ;

(c) what steps Government propose to take to provide more quarters to the employees of the two Secretaats to fulfil the recommendations of the Parliamentary Pay Committee Report 1974 ;

(d) whether Government propose provide 195 quarters in DIZ area lieu of the quartes constructed them at Vasant Vihar area as rliament Pay Body has recomended accommodation to these ployees near Parliament House ;

(e) if not, by what date these quarters at Vasant Vihar area likely to be allotted to these ployees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Rajya Sabha.

Action against builders for unauthorised constructions in Delhi

1508. SHRI J. P. GOYAL : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) thed number of FIRs registered by the Municipal Corporation of Delhi against big builders and plot owners, indulging in unauthorised constructions and encroachments on public land during the period from Ist January, 1985 to 30th April, 1986;

(b) the number of such persons against whom FIR's were registered and who have been arrested and what are their particulars ;

(c) the number of engineers of Municipal Corporation of Delhi and other employees found involved and what action has so far been taken against them ;

(d) whether Municipal Corporation's site inspectors are mainly responsible for illegal construction of residential-cum-Commercial buildings in Delhi ;

(e) if so, what steps are proposed to be taken to apprehend all such builders and site inspectors of Municipal Corporation Delhi ; and

(f) by when all the buildings new or old, in commercial areas and residential colonies are likely to be inspected to find out illegal construction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) The notification empowering the Commissioner/De-